

संघ की राजभाषा नीति

संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतराष्ट्रीय रूप है {संविधान का अनुच्छेद 343 (1)}। परन्तु हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में किया जा सकता है (राजभाषा अधिनियम की धारा 3)।

संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। परन्तु राज्यसभा के सभापति महोदय या लोकसभा के अध्यक्ष महोदय विशेष परिस्थिति में सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। {संविधान का अनुच्छेद 120}

किन प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाना है, किन के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग आवश्यक है और किन कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना है, यह राजभाषा अधिनियम 1963, [राजभाषा नियम 1976](#) और उनके अंतर्गत समय समय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निदेशों द्वारा निर्धारित किया गया है।

Official Language Policy Of The Union

Hindi in Devanagari script is the official language of the Union. The form of numeral to be used for official purposes of the Union is the international form of Indian numerals {[Article 343 \(1\) of the Constitution \(External Website that opens in a new window\)](#)}. In addition to Hindi language English language may also be used for official purposes. (Section 3 of the [Official Languages Act \(External Website that opens in a new window\)](#))

Business in Parliament may be transacted in English or in Hindi. However, the Hon'ble Chairman of the Rajya Sabha or the Hon'ble Speaker of the Lok Sabha may permit any Member to address the House in his / her mother tongue under special circumstances ([Article 120 of the Constitution \(External Website that opens in a new window\)](#)).

The purposes for which Hindi alone is to be used, the purposes for which both Hindi and English are to be used and the purposes for which English language is to be used, have been specified in the [Official Languages Act \(External Website that opens in a new window\)](#), 1963, the [Official Language Rules \(External Website that opens in a new window\)](#), 1976 and the directions issued under them from time to time by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs.

It has been the policy of the Government of India that progressive use of Hindi in the official work may be ensured through persuasion, incentive and goodwill.